जीएसटी: इस बार कोरोना कर्फ्यू में कमाई बढ़ी

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

8.50 लाख उद्योग पंजीकृत हैं पूरे प्रदेश में

उत्तर प्रदेश के लिए पिछली बार के लॉकडाउन के मुकाबले इस बार के आंशिक कोरोना कर्फ्यू ने सरकार की कमाई बढ़ा दी है। इस बार न केवल उद्योग कारोबार चलते रहे, श्रमिकों को रोजगार भी मिलता रहा। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी खजाने में बढ़ोतरी भी पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा हुई। पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस साल के अप्रैल में मिला राजस्व ज्यादा है।

सरकार के प्रवक्ता का दावा है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्य में रोज कमाने खाने वाले, पटरी दुकानदार, दैनिक मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को रोजी -रोजी का संकट नहीं हो पाया। सूबे में आर्थिक कामकाज चलते रहे।

उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। यहां कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कारोबारी गतिविधियां चल रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में करीब साढ़े आठ लाख उद्योग पंजीकृत हैं। इन उद्योगों में करीब 80 लाख लोग काम करते हैं। इसी प्रकार राज्य में करीब 80 लाख उद्योग अपंजीकृत हैं और इनमें दो करोड़ लोग काम करते हैं। राज्य में लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू में उन्हें अपना-अपना कार्य करने की छूट मिली हुई है। कोरोना महामारी की तीखी लहर के दौरान राज्य में रोज कमाने खाने वाले, पटरी दुकानदार, दैनिक मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के जीवन और जीविका को बचाने के लिए उन्हें आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपना कामकाज जारी रखने की छूट रही।

पिछले लॉकडाउन व इस बार कोरोना कर्फ्यू में मिला राजस्व

राजस्व करोड़ रुपये (अप्रैल 2020)		राजस्व करोड़ रुपये (अप्रैल 2021)
कर करेत्तर राजस्व	1298.05	11196.49
जीएसटी	670.71	5157.11

अब तेज होंगी आर्थिक गतिविधियां: यूपी सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू से 55 जिलों को पांच दिन की छूट देने के साथ ही अब उद्योग, कारोबार व आर्थिक गतिविधियां तेज करने की तैयारी में है। अब चरणबद्ध तरीके से कोरोबारी गतिविधियों को अधिक गति दी जाएगी। सूबे में औद्योगिक निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सहमति देने और उन्हें जल्द से जल्द शुरू करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्माण संबंधी बड़ी परियोजनाओं में तेजी से कार्य करने पर जोर देने के साथ ही एक जिला एक उत्पाद योजना को लेकर 'मेक इन यूपी' को आगे बढ़ावा देने पर फोकस बढ़ाया जाएगा। ओडीओपी उत्पादों को ई-कामर्स प्लेटफार्म के जरिए बढ़ावा देने के प्रयास तेज किए जाएंगे।

इसके साथ ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान रोज कमाने और खाने वाले पटरी दुकानदारों, दैनिक मजदूरों और श्रमिकों को पिछले साल की तरह इस साल भी प्रति माह 1000 रुपये का भरण-पोषण भत्ता देने का कार्य भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के फैसले के तहत अब करीब आठ लाख 80 हजार पटरी दुकानदारों को 1000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए 700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।